



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14526

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42926 वर्ष 2024

मिंदर नगर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: बृज लाल शुक्ला, रघुवंश मिश्रा, सदरुल इस्लाम जाफरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए., राहुल मिश्रा, विदित नारायण मिश्रा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित कर दी गई है।

2. हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री रघुवंश मिश्रा की ओर से अधिवक्ता श्री अश्वनी त्रिपाठी, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री विदित नारायण मिश्रा और राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 182/2024, धारा 191(2), 190, 110, 115(2), 127(2), 103(1) बीएनएस, पुलिस स्टेशन- डंकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

अभियोजन पक्ष की कहानी:

4. आवेदक ने पांच अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर 9.7.2024 को सुबह लगभग 11:00 बजे घायल कमल और जितेंद्र पर हमला किया और उनका अपहरण कर लिया। फिर उन्हें अपने घर ले जाकर दोबारा पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

5. सूचना देने वाला और अन्य व्यक्ति सह-आरोपी मिंदर (आवेदक) के घर पहुंचे, जहां उन्हें घायल जितेंद्र और कमल मिले। और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कमल को मृत घोषित कर दिया। और जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आवेदक की ओर से दलीलें:

6. आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि आवेदक का नाम एफआईआर में है, लेकिन उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है।

7. एफआईआर दर्ज करने में लगभग सोलह घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आरोप स्वतः ही झूठे हैं।

8. घायल जितेंद्र, जो मुख्य गवाह है, से एफआईआर दर्ज होने की तारीख से लगभग तेरह दिन बाद जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई है। पूछताछ में हुई यह देरी इंगित करती है कि यह स्पष्ट रूप से झूठा फंसाने का मामला है और कानूनी परामर्श के बाद कहानी गढ़ी गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. घायल जितेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि घटना वाले दिन, मृतक अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा बंशी से बात कर रहा था। तभी हर्ष और शिवम ने उसे रोका और जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहा और उससे झगड़ा करने लगे। इसी बीच, हर्ष ने अभिषेक को फोन किया, जिसके बाद अभिषेक, राज और एक अज्ञात व्यक्ति एक स्विफ्ट कार में वहाँ पहुँचे। और वे उन्हें अभिषेक के घर, नवादा गाँव ले गए। इसके बाद, हर्ष ने अपने अन्य दोस्तों को भी फोन किया। इसी बीच, उसके अन्य दोस्त, कपिल, गौरव उर्फ बंगाली, सौरभ, आशु, विकास, नरेंद्र उर्फ बघीरा, मोहित, अर्पण और हर्ष का चचेरा भाई, संजय वहाँ पहुँचे और उन सभी ने मिलकर उनकी पिटाई की। इसके बाद, घायल और मृतक व्यक्ति बेहोश हो गए और कहा जाता है कि उन्हें सह-आरोपी मिंदर (आवेदक) के घर में होश आया, जिसके बाद आवेदक और सह-आरोपी सुमित, जो संजय का भाई है, भी वहाँ पहुँचे और उन पर हमला किया।

10. मुख्य गवाह जितेंद्र ने अपने बयान में आवेदक को किसी प्रत्यक्ष कृत्य में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार, आवेदक का मामला मुख्य आरोपी हर्ष और शिवम से अलग है। अन्य आरोपियों की भूमिका को बाद में केवल परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने के लिए जोड़ा गया है। उसने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दिए गए अपने बयान में एफआईआर के संस्करण को पूरी तरह से बदल दिया है।

11. आवेदक का उक्त अपराध करने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि आवेदक घटना के अंत में अन्य आरोपियों के साथ शामिल हुआ था। यदि कोई प्रारंभिक कृत्य हुआ भी था, तो वह सह-आरोपी हर्ष और शिवम द्वारा ही किया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. मृतक की मृत्यु रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होने से काफी पहले तैयार कर ली गई थी और इसमें सूचना देने वाला पंच गवाह संख्या 2 है, लेकिन उसने उस समय किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। कानूनी परामर्श के बाद सुबह 3:02 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 18.7.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/प्रतिवादी पक्ष की ओर से तर्क:

14. जमानत याचिका का इस आधार पर कड़ा विरोध किया गया है कि मुकदमा चल रहा है और पीडब्ल्यू-1 का बयान दर्ज किया जा चुका है तथा उसकी जिरह अभी पूरी नहीं हुई है।

15. अन्य आरोपियों ने भी घायल व्यक्ति जितेंद्र को धमकी दी थी। और जितेंद्र ने सह-आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) प्रस्तुत की जा चुकी है।

16. मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर दस चोटें आई थीं। और घायल व्यक्ति को कुल चार चोटें आई थीं, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

निष्कर्ष:

17. आवेदक का मामला मुख्य आरोपी व्यक्तियों हर्ष और शिवम से अलग है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. "दोषी सिद्ध न होने पर निर्दोषता का अनुमान" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, एक नियम के रूप में जमानत और एक अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

19. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, जब तक कि दोष उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में दोहराया है।

20. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनसी 595** के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि अदालतें इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

21. माननीय ए.जी.ए./राज्य विधि अधिकारी कोई भी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके आधार पर आवेदक को जमानत देने से इनकार किया जा सके।

22. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर लगभग सोलह घंटे विलंबित है, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मुख्य गवाह जितेंद्र ने अपने बयान में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को किसी विशेष प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया है, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

23. आवेदक- **मिंदर नगर**, जो उपरोक्त मामले में अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

24. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द की जा सकती है।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

20 जनवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विकास वर्मा

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।